

जीएसटी ने बदली टैक्स व्यवस्था की तरस्वीर

आठ वर्षों में दोगुना हुआ टैक्स कलेक्शन, कारोबारी सुगमता में वृद्धि

2020-21 से 2024-25 तक
दोगुना कलेक्शन

1.5 करोड़ से ज्यादा सक्रिय
करदाता

नई दिल्ली, 30 जून. 1 जुलाई 2025 को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के आठ वर्ष पूरे होने जा रहे हैं. जीएसटी को एक सशक्त और अधिक एकीकृत अर्थव्यवस्था की नींव रखने में महत्वपूर्ण मानते हुए वर्ष 2017 में शुरू किया गया था.

जीएसटी के साथ कर अनुपालन सरल होने के साथ कारोबारियों की लागत में कमी आई और माल को बिना किसी पेशानी के देश के एक राज्य से



जीएसटी आने के साथ ही विभिन्न अप्रत्यक्ष करों की एक विस्तृत श्रृंखला को एक कर दिया गया. जीएसटी ने उत्पाद शुल्क, सेवा कर और वैट जैसे करों की जगह ले ली. इससे देश में कर प्रणाली में एकरूपता आई .

दूसरे में ले जाने की अनुमति मिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी का परिचय ‘नए भारत

के एक मार्गदर्शक कानून’ के रूप में दिया था. बीते आठ वर्षों में जीएसटी को जबरदस्त

सफलता मिली और जीएसटी कलेक्शन को लेकर लगातार वृद्धि दर्ज की गई.

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, जीएसटी कलेक्शन को लेकर बीते 5 वर्षों में लगभग दोगुना वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 11.37 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-2025 में 22.08 लाख करोड़ रुपए हो गया. जीएसटी कलेक्शन में यह तेजी अनुपालन और आर्थिक गतिविधि में निरंतर वृद्धि को दर्शाती है. आधिकारिक डेटा के अनुसार, जीएसटी कलेक्शन के साथ-साथ सक्रिय जीएसटी करदाताओं की संख्या में भी जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है, जो कि 30 अप्रैल 2025 तक बढ़कर 1,51,80,087 हो गए हैं.



अनुकूल मौसम से महंगाई पर ब्रेक

जलाशयों में भरपूर पानी, सिंचाई
को मदद

बुआई क्षेत्र 10 प्रतिशत बढ़ा,
मजदूरी में सुधार

नई दिल्ली, 30 जून. अनुकूल मौसम की स्थिति के कारण अगले छह महीनों में मुद्रास्फीति औसतन 2.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है. सोमवार को जारी एचएसबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले तीन वर्षों से उच्च आधार प्रभाव और मजबूत अनाज उत्पादन के कारण भारत में खाद्य मुद्रास्फीति लंबे समय तक कम रहने की उम्मीद है.

एचएसबीसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मजबूत भारतीय रुपए, कमोडिटी की गिरती कीमतें, चीन से आयातित मुद्रास्फीति और एक साल पहले की तुलना में कम वृद्धि

के कारण कोर मुद्रास्फीति भी नियंत्रित बनी हुई है. इन सभी कारकों को देखते हुए वित्त वर्ष 2026 में मुद्रास्फीति औसतन 3.2 प्रतिशत रहने की उम्मीद है. वित्त वर्ष 2025 भारत के अन्न भंडारों के लिए मजबूत नोट पर समाप्त हुआ, जिसमें मजबूत अनाज उत्पादन ने पर्याप्त स्टॉक स्तर सुनिश्चित किया. इस प्रचुरता से निकट भविष्य में अनाज मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलने की उम्मीद है. रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2026 में बारिश, जलाशयों का स्तर और बुआई मायने रखेंगी. वर्तमान में, वर्षा का स्तर सामान्य से 9 प्रतिशत अधिक है, जो पिछले तीन वर्षों में हुई बारिश से बहुत अधिक है. क्षेत्रवार, उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में सबसे ज्यादा बारिश हुई है. आईएमडी की उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में पूरे देश में बारिश होगी.

रिपोर्ट में कहा गया है, अच्छी बारिश से न केवल गर्मियों की बुआई को फायदा होता है, बल्कि जलाशयों को भरने में भी मदद मिलती है, जो अस्थायी रूप से बारिश रुकने की स्थिति में बफर प्रदान करते हैं और सर्दियों की बुआई के मौसम में सिंचाई का भी समर्थन करते हैं. वर्तमान में, जलाशयों का स्तर पिछले साल के साथ-साथ सामान्य भंडारण स्तरों से भी अधिक है, जिसमें दक्षिणी क्षेत्र विशेष रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रहा है.

समाचार विशेष

हिमाचल की सुकखू सरकार पर फिर नया संकट !



शिमला. हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार में एक बार फिर आपसी मतभेद और फूट की खबरें सामने आई है. जहां पार्टी के पूर्व विधायक ने अपने मंत्री पिता से इस्तीफे की अपील की है. हालांकि, बाद में उन्होंने भले ही इस सोशल मीडिया

बेटे ने मंत्री पिता से की इस्तीफे की अपील ; सियासी हलचल तेज

पोस्ट को डिलीट कर दिया, लेकिन ये बात राज्य के सियासी गलियारों जंगल की आग की तरह फैल गई.

दरअसल, कांग्रेस के पूर्व विधायक रह चुके नीरज भारती ने 19 जून को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट किया. इसमें उन्होंने अपने पिता चंदर कुमार से अपील की कि वह सुखविंदर सिंह सुकखू की सरकार से इस्तीफा दे दें. पहले से ही सरकारी कर्मचारियों के तबादले के मुद्दे को लेकर बैंकफूट पर आई सुकखू सरकार के लिए इसे एक नए झटके के रूप में देखा जा रहा है.

पिता के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार हूँ- बता दें कि मामले को तुलु पकड़ता हुआ देख मंत्री ने अपने बेटे के गुस्से को कम

करने का प्रयास किया और उनके बयान को हाताश में एक युवक प्रतिक्रिया बताया, लेकिन उन्होंने इस बात को भी माना की चल रहे तबादलों ने भानुमती का पिटारा खोल दिया है, जो सरकार के लिए गंभीर प्रशासनिक चुनौतियों का संकेत है. राज्य सरकार में मंत्री पिता ने बेटे नीरज भारती के बयान के बाद कहा कि मुद्दा खत्म हो चुका है. चीजें ठीक कर ली गई हैं. मुख्यमंत्री ने मेरे बेटे से बात की है. हालांकि, भारती को पिता की ओर से दिया गया युवा खुन वाला बयान पंसद नहीं आया. इसके बाद 20 जून को भारती ने सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट करते हुए लिखा कि उनकी लड़ाई सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए है.

मंत्री चंदर कुमार का आरोप

चंदर कुमार ने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति जो डेहर विधानसभा उपचुनाव के दौरान उनके नजदीक आया कथित तौर पर तबादले के लिए बिचौलिए का काम कर रहा है. उन्होंने उनकी विधानसभा जावाली में भी हस्तक्षेप का आरोप लगाया. इस सीट पर 2012 से 17 तक उनके बेटे विधायक थे. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि हो सकता है कि सीएम इस शख्स के बारे में नहीं जानते होंगे. रविवार शाम भारती और सीएम सुकखू के बीच मुलाकात हुई. इसके बाद उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया है. लंबे और सकारात्मक चर्चा के बाद मतभेद खत्म हो गए हैं . इस हालिया विवाद के बाद कांग्रेस नेताओं का मानना ​​है कि पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं और नेतृत्व के बीच प्रशासनिक फैसलों और स्तर के गलियारों तक पहुंच नहीं होने से फूट बढ़ी है .

फिर अकाली-भाजपा गठबंधन की चर्चा

इस बात पर फंसा पेच

लुधियाना. हल्का वेस्ट के उप चुनाव में हार के बाद फिर अकाली- भाजपा गठबंधन की चर्चा शुरू हो गई है क्योंकि अकाली- भाजपा लंबे समय तक केंद्र व राज्य की राजनीति में इकट्ठे रहे हैं और सरकार भी बनाई लेकिन कृषि कानूनों के विरोध में अकाली दल ने भाजपा का साथ छोड़ दिया और उसके बाद से दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही है. इस दौरान अकाली- भाजपा को कोई सफलता नहीं मिली. बल्कि अकाली- भाजपा एक के बाद एक चुनाव हारने की वजह से पंजाब की सियासत के हाशिए पर



जा रहे हैं. यहीं हाल हल्का वेस्ट के उप चुनाव में देखने को मिल रहा है जब अकाली- भाजपा तीसरे और

बताया जा रहा है कि इस मुद्दे पर अंदरखाने कवायद काफी देर से चल भी रही है, लेकिन अकाली दल की गुटबाजी के चलते भाजपा हमी नहीं भर रही है. हल्का वेस्ट के उप चुनाव में अकाली दल को अब तक की सबसे शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है. करीब 8 हजार वोट के साथ अकाली दल चौथे नंबर पर आया है . यहां तक कि 2022 के विधानसभा चुनाव से भी 2000 वोट डाउन हो गए हैं, क्योंकि उस समय महेश इंद्र प्रेवाल को 10 हजार से ज्यादा वोट मिले थे.

चौथे नंबर पर सीमित होकर रह गए हैं, जिसके बाद से एक बार फिर अकाली भाजपा गठबंधन की चर्चा सुनने को मिल रही है. क्योंकि अकाली- भाजपा के वोट का आंकड़ा 30 हजार से पार हो गया है, जिसके मद्देनजर सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है कि अगर अकाली- भाजपा इकट्ठे हो तभी 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की जा सकती है.



कोलकाता. पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले ममता बनर्जी को इस तरह की राजनीति करनी है, जिससे उनकी पार्टी लगातार चौथी बार जीत हासिल कर सके. गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को ममता बनर्जी ने बढ़ा

शेयर बाजार की तेजी पर ब्रेक

मुंबई, 30 जून (वार्ता) विश्व बाजार के मिलेजुले रुख के बीच स्थानीय स्तर पर ऊर्जा, ऑटो, बैंकिंग, धातु और रियल्टी समेत दस समूहों में हुई बिकवाली से शेयर बाजार की पिछले लगातार चार दिन की तेजी आज थम गई.बीएसई का तीस शेयरों वाला संवेदी सूचकांक संसेक्स 452.44 अंक की गिरावट लेकर 83606.46 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 120.75 अंक लुढ़ककर 25517.05 अंक पर आ गया. बीएसई की दिग्गज कंपनियों के विपरीत मझौली और छोटी कंपनियों के शेयरों में जमकर लिवाली हुई, जिससे बाजार को समर्थन मिला. मिडकैप 0.67 प्रतिशत की छलांग लगाकर 46,854.46 अंक और स्मॉलकैप 0.81 प्रतिशत उछलकर 54,690.91 अंक पर बंद हुआ.

भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था

भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन की
उम्मीद : निर्मला सीतारमण

अच्छे मानसून और कृषि से मिलेगी
मजदूती

नई दिल्ली, 30 जून. भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है और आने वाले समय में अच्छे मानसून और कृषि के कारण और बेहतर प्रदर्शन कर सकती है. यह बयान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से सोमवार को दिया गया.

आरबीआई के ताजा डेटा के मुताबिक, कृषि, निर्माण और सेवा क्षेत्रों के मजबूत प्रदर्शन के दम पर 2024-25 की चौथी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर बढ़कर 7.4 प्रतिशत हो गई, जिसके परिणामस्वरूप पूरे वित्तीय वर्ष के लिए विकास दर

श्रम-प्रधान इकाइयों को सहायता दी जाएगी



नीतिगत समर्थन दिया जाएगा . उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में सभी बजट में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली इस सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हम कुछ ठोस नीतियां बनाएं जो लोगों, खासकर एमएसएमई की मदद करें .

वित्त मंत्री ने आगे कहा कि हमारी नीति स्पष्ट है कि श्रम-प्रधान इकाइयों को सहायता दी जाएगी. वित्त मंत्री ने कहा, हमने स्पष्ट किया है कि हस्तशिल्प, हस्तनिर्मित सामान आदि को सहायता मिलेगी. ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम एक (श्रम) और दूसरे (पूंजी/तकनीक) के बीच अंतर करें. विनिर्माण, चाहे वह रोजगार-प्रधान हो या स्वचालित, उसे

6.5 प्रतिशत पहुंच गई थी.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर अपना मीडिया इंटरव्यू पोस्ट करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह विकास दर जारी रहेगी और अच्छे मानसून के कारण अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन में सुधार होगा. उन्होंने आगे कहा कि हमारे बाजारों की गहराई वास्तव में दिख

रही है और इससे खुदरा विक्रेताओं और आम नागरिकों को लाभ हो रहा है.वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, हमारी प्रणालियां पारदर्शी और डिजिटल हैं और घर बैठे ही उन तक पहुंचा जा सकता है. व्यक्ति दूसरों की मदद पर निर्भर रहने के बजाय खुद ही यह काम कर सकते हैं.

यूएई बना अमीरों का नया ठिकाना

गोल्डन वीजा और टैक्स राहत से करोड़पतियों का रुझान बढ़ा

नई दिल्ली, 30 जून. संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) दुनिया के अति-धनी व्यक्तियों के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है. निचामक सुधारों, अनुकूल कर नीतियों और गोल्डन वीजा जैसे दीर्घकालिक निवास विकल्पों के कारण यूएई वैश्विक करोड़पतियों को आकर्षित कर रहा है.

ग्लफ़ न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, हेनले एंड पार्टनर्स प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि अकेले 2025 में कम से कम 9,800 करोड़पति यूएई में स्थानांतरित हो सकते हैं, जो स्थिरता और रणनीतिक लाभ चाहने वाले उच्च-निवल मूल्य वाले व्यक्तियों के लिए देश के



आकर्षण को रेखांकित करता है. कई हाई-प्रोफाइल अरबपति वैश्विक स्तर पर यूएई में स्थानांतरित हुए हैं. इनमें नॉर्वेजियन मूल के शिपिंग डिग्गज जॉन फ्रेडरिकसेन शामिल हैं, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के नॉन-डॉम्ड कर व्यवस्था को खत्म करने के फैसले को अपनी लंदन से यूएई स्थानांतरण का प्रमुख कारण बताया. फ्रेडरिकसेन, जो कभी यूके के नौवें सबसे अमीर व्यक्ति थे, ने अपने व्यावसायिक संचालन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लंदन से यूएई में स्थानांतरित कर दिया है.

भारत की विदेशी परिसंपत्तियां बढ़ीं 105.4 अरब डॉलर

आरक्षित परिसंपत्तियों का योगदान
रहा 54 प्रतिशत

शुद्ध विदेशी ढावों में 31.2 अरब
डॉलर की गिरावट



के कारण हुई है.आंकड़ों से यह भी सामने आया है कि भारत की कुल विदेशी वित्तीय परिसंपत्तियों में हुई वृद्धि का 72 प्रतिशत से अधिक हिस्सा इन तीन घटकों से आया है, जिसमें अकेले आरक्षित परिसंपत्तियों का योगदान 54 प्रतिशत से अधिक रहा. मुद्रा और जमा के साथ-साथ प्रत्यक्ष निवेश

ने भी भारतीय निवासियों द्वारा धारित विदेशी परिसंपत्तियों की समग्र वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया. आरबीआई ने कहा है कि, भारत की विदेशी वित्तीय परिसंपत्तियों में वृद्धि का 72 प्रतिशत से अधिक हिस्सा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, मुद्रा और जमा में वृद्धि के कारण था.2024-25 के दौरान, भारत की कुल बाहरी वित्तीय परिसंपत्तियां 105.4 अरब डॉलर बढ़ीं, जबकि इसकी बाहरी वित्तीय देनदारियां 74.2 अरब डॉलर बढ़ीं. परिणामस्वरूप, वर्ष के दौरान भारत पर गैर-निवासियों के शुद्ध ढावों में 31.2 अरब डॉलर की कमी आई.

अखिलेश ने पूछा कहां से लड़ेंगे चुनाव ?

तेज प्रताप ने बताया अपना प्लान

पटना. इस समय सियासत के केंद्र में बिहार विधानसभा चुनाव है. साल के अंत में होने वाले चुनाव में एनडीए और महागबंधन में लड़ाई है. राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों की नजरें बिहार के दो नेताओं पर टिकी हुई हैं, जिसमें पहले नेता लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेज प्रताप यादव हैं तो दूसरे नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं. सब के मन में एक ही सवाल है कि क्या चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे. इसके साथ ही लोग यह भी जानने को उत्सुक हैं कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव का राजद में वापसी होगी. यदि वापसी नहीं होती तो तेज प्रताप चुनाव लड़ेंगे या नहीं.

नीतीश कुमार के दोबारा मुख्यमंत्री बनने को लेकर कुछ भी साफ नहीं हो पा रहा है, लेकिन तेज प्रताप के सियासी भविष्य को लेकर एक नया अपडेट



मिला है. यह अपडेट सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो से आया है, जिसमें तेज प्रताप यादव यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से बातचीत कर रहे हैं. अखिलेश यादव का तेज प्रताप यादव से न केवल सियासी संबंध हैं, बल्कि दोनों राजनीतिक परिवारों में रिश्तेदारी भी है. यही वजह है कि अखिलेश यादव और तेज प्रताप अक्सर एक दूसरे से फोन पर बातचीत करते रहते हैं. पार्टी और परिवार से बेदखली के बाद तेज प्रताप ने अखिलेश यादव से शायद पहली बार बातचीत की.

इतना ही नहीं ममता बनर्जी ने जगन्नाथ मंदिर बनने के बाद पहली रथयात्रा के मौके पर प्रदेश के सभी नागरिकों को भगवान जगन्नाथ का प्रयाद पहुंचाने का फैसला किया है . इस काम के लिए हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी हिडको को कहा गया है. सरकार ने इसके लिए 42 करोड़ रुपए के फंड की मंजूरी दी है. विडम्बना यह है कि भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है. भाजपा ने कहा कि सरकार की इस ईकाई का काम बुनियादी ढांचे का विकास करना है उसको प्रसाद बाटने के काम में लगाया जा रहा है. सोचें, अब तक भाजपा की सरकारें हिंदू धर्म को प्रमोट करने के लिए सरकारी फंड का इस्तेमाल करती रही है .

शामिल हुए. बाद में इस मंदिर को जगन्नाथ धाम कहने पर विवाद शुरू हुआ. पुरी मंदिर के पुजारियों और ओडिशा के लोगों ने विरोध किया कि धाम सिर्फ जगन्नाथपुरी को ही कहा जा

सकता है. हालांकि ममता बनर्जी पर इसका कोई असर नहीं हुआ. मां काली के साथ साथ ममता भगवान जगन्नाथ के नाम से भी भगाली अस्मिता का दांव खेल रही हैं.